भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 197
(जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण,1947 (शक) को दिया जाना है)

परिवारों की घटती बचत

197. **श्री राव राजेन्द्र सिंहः**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में परिवारों की घटती बचत में गिरावाट का संज्ञान लिया है जो वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 18.1 प्रतिशत हो गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) पारिवारिक और निजी बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्य नीतिगत उपाय किए हैं, ताकि घरेलू निवेश को सही किया जा सके; और
(ग) क्या सरकार ने घरेलू बचत में गिरावट का देश के विकास और राजकोषीय स्थिरता पर लंबे समय में पड़ने वाले असर का आकलन किया है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार, 2022-23 में घरेलू बचत ₹50.1 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹54.61 लाख करोड़ हो गई है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, घरेलू बचत वर्ष 2022-23 में 18.6 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 18.1 प्रतिशत हो गई।

(ख): सरकार का मुख्य बल व्यापार में सुगमता, कौशल विकास, रोज़गार सृजन, समावेशी मानव संसाधन विकास और अवसंरचना सृजन पर है, जिससे घरेलू आय और बचत में वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। इसके अलावा, ₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर नई आय कर छूट और हाल ही में जीएसटी दर को कम करने संबंधी उपायों से घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

(ग): सरकार घरेलू बचत समेत मुख्य आर्थिक मानदंडों की प्रवृत्ति पर गहन दृष्टि रखती है, साथ ही आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता पर उनके असर की भी निगरानी करती है। अभी मज़बूत घरेलू मांग, कम होती महंगाई, बेहतर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और निरंतर राजकोषीय अनुशासन के कारण, भारतीय अर्थव्यवस्था के मैक्रोइकोनॉमिक फंडामेंटल्स मज़बूत बने हुए हैं।

*****